जीएसटी को लेकर चिंताओं के बीच सरकार ने कहा

राजस्व बंटवारे में केंद्र और राज्य बराबर के हकदार

नई दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा)।

केंद्र के प्रस्तावित दो स्लैब वाले जीएसटी से राजस्व पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताओं के बीच सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि केंद्र राज्यों के साथ राजस्व बंटवारे में समान भागीदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगली पीढ़ी का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मध्यम वर्ग का समर्थन करता है और खपत बढ़ने के कारण इससे समय के साथ राजस्व बढ़ने की उम्मीद है।

इस समय जीएसटी ढांचे के तहत राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभाज्य कर पूल में केंद्र के हिस्से का 41 फीसद राज्यों को आबंटित किया जाता है।

एक सरकारी सूत्र ने कहा कि जीएसटी में क्या संग्रह हो रहा है और क्या संग्रह होगा, इस पर केंद्र की समान चिंताएं हैं। जीएसटी परिषद का सदस्य होने के नाते केंद्र और राज्य, दोनों समान भागीदार हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह उम्मीद करना उचित है कि भारत सरकार राज्यों को क्षतिपूर्ति करेगी? इस समय जीएसटी एक चार स्तरीय संरचना है, जिसमें कर की दरें पांच फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद हैं। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं पर या तो शून्य या पांच फीसद की दर से कर लगाया जाता है, और विलासिता तथा अहितकर वस्तुओं पर 28 फीसद की दर से कर लगाया जाता है।

कुल जीएसटी राजस्व में पांच फीसद स्लैब की सात फीसद हिस्सेदारी है। दूसरी ओर 12 फीसद स्लैब की पांच फीसद, 18 फीसद स्लैब की 65 फीसद और 28 फीसद स्लैब की 11 फीसद हिस्सेदारी है। केंद्र ने जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह को पांच फीसद और 18 फीसद की दो स्तरीय दर संरचना और लगभग 5-7 वस्तुओं के लिए 40 फीसद की दर का प्रस्ताव दिया है।

18 फीसद कर ढांचे का जीएसटी राजस्व में प्रमुख योगदान बना रहेगा

नई दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा)।

केंद्र के दो-स्तरीय जीएसटी ढांचे और 40 फीसद की विशेष कर दर के प्रस्ताव को यदि लागू किया जाता है, तो 18 फीसद कर स्लैब जीएसटी राजस्व में प्रमुख योगदान देने वाला बना रहेगा। वर्तमान में, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में चार स्लैब... पांच फीसद, 12, 18 और 28 फीसद... हैं। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं पर या तो छूट है या उन पर पांच फीसद कर लगता है, जबकि विलासिता और समाज के नजरिये से अहितकर वस्तुओं पर 28 फीसद की उच्चतम दर लागू होती है।

पांच फीसद स्लैब कुल जीएसटी राजस्व में लगभग सात फीसद का योगदान देता है, जबकि 18 फीसद स्लैब का योगदान 65 फीसद है। 12 फीसद और 28 फीसद स्लैब जीएसटी संग्रह में क्रमशः लगभग पांच फीसद और 11 फीसद का योगदान करते हैं। केंद्र ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह के समक्ष पांच और 18 फीसद की दो-स्तरीय जीएसटी संरचना के साथ-साथ कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 फीसद की विशेष दर का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में मौजूदा 12 और 28 फीसद कर स्लैब को समाप्त करने का प्रावधान है। सूत्र ने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार, 18 फीसद स्लैब का जीएसटी राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा बना रहेगा। हमें उम्मीद है कि मात्रा बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी जिससे जीएसटी राजस्व को मौजूदा स्तर से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र के प्रस्ताव के तहत वर्तमान 12 फीसद स्लैब में शामिल 99 फीसद वस्तुओं को पांच फीसद में तथा 28 फीसद स्लैब में शामिल 90 फीसद वस्तुओं और सेवाओं को 18 फीसद स्लैब में शामिल किया जाएगा।

साथ ही, 28 फीसद के स्लैब में शामिल 90 फीसद वस्तुएं और सेवाएं 18 फीसद के स्लैब में आ जाएंगी। केवल पांच से सात वस्तुएं ही 40 फीसद की दर तक जाएंगी। औसत मासिक जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया जो 2021-22 में 1.51 लाख करोड़ रुपए था। जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। पंजीकृत करदाताओं की संख्या 2017 के 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ से अधिक हो गई है।

सीतारमण मंत्री समूह की बैठक को करेंगी संबोधित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी में सुधारों को लेकर बुधवार को राज्यों के मंत्रियों के समूह की एक बैठक को संबोधित करेंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इन सुधारों के तहत कर दरों में कटौती होगी और आम इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। केंद्र ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह के समक्ष पांच और 18 फीसद की दो-स्तरीय जीएसटी संरचना के साथ-साथ कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 फीसद की विशेष दर का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों ने के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा 12 और 28 फीसद की कर दरों को हटाने का प्रस्ताव है। 20 और 21 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली राज्यों के मंत्री समूह की दो दिन की बैठक में सुधार प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य जीएसटी सुधार प्रस्ताव के पीछे केंद्र के दृष्टिकोण को सामने रखना है। हालांकि, केंद्र इस मंत्री समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति और उनके संबोधन से मंत्री समूह को केंद्र के प्रस्ताव के पीछे की सोच व विचार को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छह सदस्यीय मंत्री समूह के संयोजक हैं।

जीएसटी सुधारों की घोषणा से शेयर बाजार में रौनक, सूचकांक 676 अंक चढ़ा

दिवाली तक जीएसटी कर स्लैब में बड़े सुधार किए जाने की घोषणा से वाहन एवं टिकाऊ उपभोक्ता कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त लिवाली से सोमवार को स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी रही। सूचकांक 676 अंक और निफ्टी 246 अंक चढ़कर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक 676.09 अंक यानी 0.84 फीसद बढ़कर 81,273.75 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,168.11 अंक चढ़कर 81,765.77 अंक पर पहुंच गया था। नैशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों सूचकांक निफ्टी भी 245.65 अंक यानी एक फीसद चढ़कर 24,876.95 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान यह 390.7 अंक की बढ़त के साथ 25,022 तक पहुंच गया था। विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक रेटिंग एजंसी एसएंडपी की तरफ से भारत की साख को बढ़ाए जाने से भी निवेशक धारणा को बल मिला। सूचकांक की कंपनियों में मारुति का शेयर सबसे अधिक 8.94 फीसद के लाभ में रहा। बजाज फाइनेंस में पांच फीसद, अल्ट्राटेक सीमेंट में 3.71 और बजाज फिनसर्व में 3.7 फीसद की तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ट्रेंट के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि, आइटीसी का शेयर 1.26 फीसद के नुकसान में रहा।

खबर कोना

56.04 करोड़ पीएम जनधन खातों में से 23 फीसद निष्क्रिय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अगस्त।

प्रधानमंत्री जनधन खातों से ग्राहकों का मोहभंग हो रहा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बताया कि कुल 56.04 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में से 23 फीसद निष्क्रिय हैं। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 31 जुलाई 2025 के अंत तक 56.03 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 13.04 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं। मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2.75 करोड़ निष्क्रिय जन धन खाते हैं, इसके बाद बिहार में 1.39 करोड़ और मध्य प्रदेश में 1.07 करोड़ ऐसे खाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के 18 फरवरी 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी बचत खाते में दो साल से अधिक समय तक कोई लेन-देन नहीं होता है। तो उसे निष्क्रिय माना जाना चाहिए।

माल एवं सेवा कर में कटौती से एसी कीमतें 2,500 रुपए तक घटेंगी

नई दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा)।

एअर कंडीशनर (एसी) पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को मौजूदा 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करने के सरकार के प्रस्ताव से उपकरण विनिर्माताओं को आगामी त्योहारों के दौरान अच्छी बिक्री की उम्मीद है। इससे विभिन्न माडल के आधार पर एअर कंडीशनर (एसी) की कीमतें 1,500 रुपए से 2,500 रुपए तक कम हो जाएंगी। सरकार द्वारा हाल ही में आयकर में कटौती और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में संशोधन के बाद कीमतों में यह कटौती होने जा रही है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. Initial Public Offer of Equity Shares (as defined below) on the main board of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE", and together with BSE, the "Stock Exchanges") in compliance with Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").

(Please scan the QR code to view the corrigendum)

PATEL RETAIL LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Patel Retail Private Limited" at Ambernath, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated June 13, 2007 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai ("**RoC**"). Thereafter, our Company was converted into a public limited company, approved vide shareholders' resolution dated July 18, 2023, pursuant to which the name of our Company was changed to "Patel Retail Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name on conversion to public limited company was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai dated August 28, 2023. For details of changes in name and the registered office of the Company, see ***"History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company"*** and ***"History and Certain Corporate Matters – Changes in the Registered Office"*** on page 405 of the red herring prospectus dated August 07, 2025 (**"RHP"** or **"Red Herring Prospectus"**) filed with RoC.

Registered & Corporate Office: Plot No. M-2, Anand Nagar, Additional MIDC, Ambernath (East) - 421506, Maharashtra, India. **Contact Person:** Prasad R Khopkar, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 7391043825; **Email:** cs@patelrpl.net; **Website:** www.patelrpl.in; **Corporate Identity Number:** U52100MH2007PLC171625

PROMOTERS OF OUR COMPANY: DHANJI RAGHAVJI PATEL, BECHAR RAGHAVJI PATEL, HIREN BECHAR PATEL AND RAHUL DHANJI PATEL

NOTICE TO INVESTORS: CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED AUGUST 07, 2025 (THE "CORRIGENDUM")

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 95,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF PATEL RETAIL LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("THE OFFER"). THE OFFER COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF UP TO 85,18,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 10,02,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 7,68,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS BY DHANJI RAGHAVJI PATEL, AND UP TO 2,34, 000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS BY BECHAR RAGHAVJI PATEL (TOGETHER, "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS").

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 51,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●] % AND [●] %, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. OUR COMPANY MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("BRLM"), OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹ 20 ON THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT").

A PRE-IPO PLACEMENT WAS UNDERTAKEN BY THE COMPANY ON NOVEMBER 27, 2024, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, OF 5,00,000 EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹10 EACH AT A PRICE OF ₹ 300 PER SHARE, AGGREGATING TO ₹1500.00 LAKHS.

With reference to the Red Herring Prospectus dated August 07, 2025 filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges, potential bidders may note the following:
On page 567 of the RHP, the table indicating Maximum Bid in the ***"Offer Structure"*** section shall be read as follows:

Particulars	Eligible Employees	QIBs [1]	Non-Institutional Bidders / Investors	Retail Individual Bidders / Investors
Maximum Bid	Such number of Equity Shares in multiples of [●] Equity Shares, so that the maximum Bid Amount by each Eligible Employee in Eligible Employee Portion does not exceed ₹5,00,000 (net of Employee Discount, if any).	Such number of Equity Shares in multiples of [●] Equity Shares of face value of ₹10/- each not exceeding the size of the **Net** Offer (excluding the Anchor Investor Portion), subject to applicable limits under applicable law.	Such number of Equity Shares in multiples of [●] Equity Shares of face value of ₹10/- each not exceeding the size of the **Net** Offer (excluding the QIB Portion), subject to limits prescribed under applicable law.	Such number of Equity Shares of face value of ₹10/- each in multiples of [●] Equity Shares so that the Bid Amount does not exceed ₹2,00,000.

The information above modifies and updates the information (as applicable) in the RHP. The RHP accordingly stands amended to the extent stated hereinabove and the above changes are to be read in conjunction with the RHP. Please note that this Corrigendum does not reflect any other changes that have occurred between the date of filing of the RHP and the date of the Corrigendum, and the relevant changes shall be reflected in the Prospectus as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges.
This Corrigendum shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com, the website of our Company www.patelrpl.in and the website of the Book Running Lead Manager www.fedsec.in. All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER (BRLM)

Fedex Securities Private Limited
Address: B7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (East), Mumbai- 400057, Maharashtra, India
Telephone: +91 8104985249;
Email: mb@fedsec.in;
Contact person: Saipan Sanghvi
Website: www.fedsec.in;
SEBI Registration No.: INM000010163

REGISTRAR TO THE OFFER

Bigshare Services Private Limited
Address: Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai- 400093, Maharashtra, India
Telephone: 022-62638200; **Email:** ipo@bigshareonline.com
Investor Grievance email: investor@bigshareonline.com
Contact person: Babu Rapheal
Website: www.bigshareonline.com
SEBI Registration No.: INR000001385

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Prasad R Khopkar
PATEL RETAIL LIMITED
Plot No. M-2, Anand Nagar, Additional MIDC, Ambernath (East) - 421506, Maharashtra, India
Telephone: +91 7391043825
Email: cs@patelrpl.net
Website: www.patelrpl.in

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-offer or post-offer related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM.

For **PATEL RETAIL LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Prasad R Khopkar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ambernath
Date : August 18, 2025

PATEL RETAIL LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated August 07, 2025 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Fedex Securities Private Limited at www.fedsec.in, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Company at www.patelrpl.in. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section *"Risk Factors"* beginning on page 40 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but should only rely on the information included in the RHP filed by the Company with the RoC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**), or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sale occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Applications may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States.

CONCEPT

कैग रपट

रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में परिचालन खर्च 5,000 करोड़ रुपए कम दिखाया

नई दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा)।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रपट में कहा गया है कि भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपने परिचालन खर्च को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक कम करके दिखाया। हाल ही में संसद के पटल पर रखी गई इस रपट में कहा गया है कि रेलवे ने अपनी कमाई एवं खर्च के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2,517.38 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दिखाया, लेकिन यात्री सेवाओं के घाटे का माल ढुलाई से हुई कमाई से समायोजन किए जाने पर 5,257.07 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा सामने आया।

बही-खाते के आडिट में पाया गया कि रेलवे का कुल कार्यशील व्यय (विभिन्न कोषों में प्रावधान सहित) 2,37,659.58 करोड़ रुपए रहा जबकि यात्री परिवहन, माल ढुलाई एवं अन्य सेवाओं से इसकी आय 2,40,176.96 करोड़ रुपए रही। इस तरह रेलवे के बही-खाते में 2,517.38 करोड़ रुपए का अधिशेष नजर आया। हालांकि, यात्री एवं अन्य कोच सेवाओं पर दी जाने वाली 'क्रास-सबसिडी' से संबंधित आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन अवधि में रेलवे का कुल खर्च 2,45,393.71 करोड़ रुपए और कुल आय 2,40,136.64 करोड़ रुपए रही।

इस तरह रेलवे को कुल 5,257 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कैग की रपट कहती है कि इस आंकड़े से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वित्तीय लेन-देन के सार में कुल कार्यशील व्यय को कम करके दिखाया गया है। खर्च को कम दिखाने से वास्तविक परिचालन अनुपात (ओआर) नहीं दिखेगा। इसके मुताबिक, रेलवे ने 2022-23 में ओआर 98.10 फीसद दिखाया जबकि सही खर्च जोड़ने पर यह 101.33 फीसद होता। बजट अनुमान में इसका लक्ष्य 96.98 फीसद रखा गया था। कैग ने बताया कि रेलवे ने यात्री सेवाओं से 74,289.66 करोड़ रुपए और माल ढुलाई सेवाओं से 1,65,846.98 करोड़ रुपए कमाए। इसका यात्री सेवाओं पर खर्च 1,34,330.84 करोड़ रुपए और माल सेवाओं पर 1,11,062.87 करोड़ रुपए रहा।

महाराष्ट्र में भारी बारिश से गई सात लोगों की जान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अगस्त।

भारी बारिश ने सोमवार को कई राज्यों में कहर बरपाया। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा, जहां बारिश के कारण सात लोगों की मौत हो गई है। लगातार बारिश से नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंस गए, जिसके कारण अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण करीब 400 सड़कें बंद हो गईं।

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से प्रभावित गांव में मलबे से दो और शव बरामद किए गए, जिससे 14 अगस्त की आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। रुक-रुक कर हो रही बारिश के बावजूद तलाशी अभियान पांचवें दिन भी जारी रहा। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से शहर थम सा गया, जिसके चलते बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएससी) को मंगलवार को विद्यालय और कालेज में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। देश की आर्थिक राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार को नौ घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। मुंबई में लगातार बारिश के कारण जलभराव से प्रभावित चेंबूर के एक अस्पताल में भर्ती होने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को अपने बीमार परिजनों को पीठ पर लादकर बीएमसी द्वारा संचालित 'मां जनरल अस्पताल' तक जाते देखा गया।

एक अधिकारी ने बताया कि शाम तक स्थिति नियंत्रण में आ गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में लगातार बारिश के बीच बाढ़ में 200 से ज्यादा लोग फंस गए, जिससे अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना बुलानी पड़ी। राज्य सचिवालय में एक बैठक में बारिश की स्थिति की समीक्षा के बाद फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुईं, कुछ को 'गो-अराउंड' (विमान के उतरने को बीच में रोककर फिर से उड़ान भरना) करना पड़ा और एक उड़ान का मार्ग परिवर्तित किया गया। भारी बारिश के कारण दृश्यता कम हो गई और पहुंच मार्गों पर भीड़ बढ़ गई, जिससे आने-जाने वाले यात्रियों को असुविधा हुई। मुंबई में सोमवार को छह से आठ घंटों में 177 मिलीमीटर बारिश हुई।

मुंबई में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया। एक इलाके से गुजरती छात्राएं।

ठाणे जिले में, कल्याण के एक पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे चार घर क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें कोई घायल नहीं हुआ। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ठाणे और पालघर जिलों में 18-19 अगस्त के लिए लाल चेतावनी जारी किए जाने के बाद, अधिकारियों ने मंगलवार को स्कूल और कालेज में छुट्टी घोषित कर दी है। जम्मू-कश्मीर के बादल फटने से प्रभावित चिशोती गांव में, बचाव दल कई स्थानों पर, खासकर एक लंगर (सामुदायिक रसोई) स्थल के पास, मलबे को हटाने के लिए काम कर रहे हैं।

वे अर्थमूवर और खोजी कुत्तों सहित मशीनों का उपयोग कर मलबे को हटा रहे हैं। आज दोपहर दो शव बरामद किए गए, जिनमें से एक महिला का था। कुल 167 लोगों को बचाया गया, जबकि आज सुबह सूची में नए सिरे से संशोधन के बाद लापता लोगों की संख्या घटकर 39 रह गई। सेना की जम्मू स्थित वाइट नाइट कोर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि बल की पांच राहत टुकड़ियां बचाव व राहत कार्यों में लगी हुई हैं।